

परमाणु नीति : खतरनाक है यह अमेरिकी सोच

अमेरिका द्वारा अपनी परमाणु रणनीति की समीक्षा करते हुए कम क्षमता वाले परमाणु हथियारों (लो-यील्ड न्यूक्लियर वेपन्स) को प्राथमिकता देने का संकेत केवल एक सैन्य नीति में बदलाव नहीं, बल्कि वैश्विक सुरक्षा व्यवस्था के लिए गंभीर चेतावनी है. पेंटागन का तर्क है कि चीन और रूस की बढ़ती सैन्य शक्ति के बीच अमेरिका को ऐसे परमाणु विकल्प चाहिए, जिनका उपयोग क्षेत्रीय संघर्षों में किया जा सके . लेकिन यह तर्क जितना व्यावहारिक दिखाई देता है, उतना ही खतरनाक भी है. परमाणु हथियारों को 'सीमित उपयोग' का माध्यम मान लेना विश्व को एक ऐसे दौर में धकेल सकता है, जहां परमाणु युद्ध की आशंका पहले से कहीं अधिक बढ़ जाएगी. द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूरी दुनिया ने यह सिद्धांत स्वीकार किया था कि परमाणु हथियार युद्ध लड़ने के लिए नहीं,

बल्कि युद्ध रोकने के लिए हैं. इसी सोच ने पिछले आठ दशकों में महाशक्तियों को प्रत्यक्ष परमाणु टकराव से दूर रखा. अब यदि अमेरिका स्वयं यह संदेश देता है कि छोटे परमाणु हथियारों का उपयोग किसी क्षेत्रीय युद्ध में संभव है, तो यह स्थापित परमाणु प्रतिरोधक सिद्धांत को कमजोर करेगा. इसका सबसे बड़ा दुष्परिणाम यह होगा कि अन्य परमाणु संपन्न देश भी अपने शस्त्रागार और सैन्य सिद्धांतों में इसी प्रकार के बदलाव करेंगे. अमेरिका चीन की बढ़ती परमाणु क्षमता, रूस के विशाल टैक्टिकल परमाणु भंडार और न्यू स्टार्ट संधि के कमजोर पड़ने का हवाला दे रहा है. ये चिंताएं वास्तविक हो सकती हैं, लेकिन उनका समाधान हथियारों की नई दौड़ नहीं है. इतिहास बताता है कि हर नई सैन्य तकनीक ने प्रतिद्वंद्वी देशों को भी उसी दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है. परिणामस्वरूप सुरक्षा

बढ़ने के बजाय असुरक्षा और अविश्वास का दायरा विस्तृत हुआ है. सबसे गंभीर प्रश्न यह है कि किसी संघर्ष के दौरान छोड़ी गई मिसाइल में कम क्षमता का परमाणु वारहेड है या अत्यधिक विनाशकारी, इसका पता विरोधी देश तत्काल नहीं लगा सकता. ऐसी स्थिति में जवाब भी अधिकतम शक्ति के साथ दिया जा सकता है. अर्थात सीमित परमाणु हमला कुछ ही मिनटों में पूर्ण परमाणु युद्ध का रूप ले सकता है. यहीं वह खतरा है, जिसकी ओर हथियार नियंत्रण विशेषज्ञ लगातार चेतावनी देते रहे हैं. भारत के लिए यह घटनाक्रम विशेष चिंता का विषय है. भारत ने हमेशा 'विश्वसनीय न्यूनतम प्रतिरोधक क्षमता' और 'पहले उपयोग नहीं' की नीति को अपनाकर जिम्मेदार परमाणु शक्ति होने का परिचय दिया है. भारत का मानना रहा है कि परमाणु हथियार राजनीतिक प्रतिरोध के साधन हैं, युद्ध

के नहीं. यदि विश्व की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति परमाणु हथियारों के सीमित उपयोग को स्वीकार्य बनाने की दिशा में बढ़ती है, तो एशिया-प्रशांत क्षेत्र के साथ-साथ दक्षिण एशिया का सामरिक संतुलन भी प्रभावित हो सकता है. इसका असर भारत की सुरक्षा और उसकी विदेश नीति दोनों पर पड़ेगा. आज आवश्यकता नई परमाणु प्रतिस्पर्धा की नहीं, बल्कि नए हथियार नियंत्रण समझौतों की है. अमेरिका, रूस और चीन को संवाद के माध्यम से विश्वास बहाली की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए. संयुक्त राष्ट्र और अन्य वैश्विक संस्थाओं को भी परमाणु निरस्त्रीकरण की प्रक्रिया को पुनर्जीवित करने के लिए सक्रिय भूमिका निभानी होगी. दरअसल,मानवता की सुरक्षा परमाणु हथियारों के नए विकल्प खोजने में नहीं, बल्कि उनके उपयोग की संभावना को हमेशा के लिए समाप्त करने में निहित है.

कुटुम्ब प्रबोधन की चीखती अनिवार्यता

सभ्यताएँ केवल ऊँची-ऊँची इमारतों, तेज़ इंटरनेट, कृत्रिम बुद्धिमत्ता या आर्थिक प्रगति से महान नहीं बनतीं । किसी भी राष्ट्र की वास्तविक पहचान इस बात से होती है कि वह अपने माता-पिता, बुजुर्गों, गुरुजनों और परिवार जैसी मूल संस्थाओं के प्रति कितना संवेदनशील है। भारतीय संस्कृति ने हजारों वर्षों से मनुष्य को यही शिक्षा दी है—मातृदेवो भवः, पितृदेवो भवः, आचार्यदेवो भवः। अर्थात माता, पिता और गुरु केवल रिश्ते नहीं, बल्कि जीवन के प्रथम देवता हैं। यही कारण है कि भारतीय समाज ने श्रवण कुमार और भगवान श्रीराम जैसे आदर्शों को केवल कथाओं में नहीं, बल्कि जीवन-मूल्यों के रूप में स्थापित किया। आज भारत डिजिटल युग के स्वर्णिम दौर से गुजर रहा है। मोबाइल ने दुनिया को हथेली पर ला दिया है और कृत्रिम बुद्धिमत्ता नई संभावनाओं के द्वार खोल रही है। विज्ञान और तकनीक का स्वागत होना चाहिए, किंतु चिंता तब उत्पन्न होती है जब तकनीक सुविधा का माध्यम न रहकर संवेदनाओं का

‘कुटुम्ब प्रबोधन’ हमें याद दिलाता है कि सप्ताह में कुछ समय परिवार के साथ बैठना, एक साथ भोजन करना, घर के बुजुर्गों के अनुभव सुनना और बच्चों को परिवार के प्रति उत्तरदायित्व सिखाना केवल पारिवारिक परंपरा नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण का आधार है। यदि परिवार मजबूत रहेगा, तो समाज भी मजबूत रहेगा और समाज मजबूत होगा, तो राष्ट्र भी सुदृढ़ बनेगा।

विकल्प बनने लगे। जब रिश्तों का मूल्य ऑनलाइन ट्रांसफर से आँका जाने लगे और मोबाइल स्क्रीन किसी प्रियजन के स्पर्श की जगह लेने लगे, तब समाज को आत्ममंथन करना ही पड़ता है। पिछले दिनों सामने आई दो घटनाएँ इसी आत्ममंथन के लिए विवश करती हैं। पहली घटना हरियाणा के सोनीपत स्थित ‘अपना घर’ वृद्धाश्रम की है। मुंबई के कभी प्रतिष्ठित कपड़ा व्यापारी रहे 74 वर्षीय शिवचरण रामचंद्रन गुप्ता जीवन के अंतिम वर्षों में वृद्धाश्रम में रह रहे थे। व्यापार में भारी नुकसान के बाद वे अपनी पत्नी के साथ आश्रम पहुँचे थे। पत्नी के निधन के बाद वे पूरी तरह अकेले पड़ गए। उनकी तीनों बेटियों को उनकी गंभीर बीमारी की सूचना लगभग बीस दिन पहले दे दी गई थी, लेकिन कोई भी उनसे मिलने नहीं पहुँची। शिवचरण जी के निधन के बाद जो हुआ, उसने पूरे समाज को झकझोर दिया। बेटियों ने अंतिम संस्कार के लिए 25,100 ऑनलाइन भेज दिए और अनुरोध किया कि पूरी प्रक्रिया उन्हें वीडियो कॉल पर दिखा दी जाए। इतना ही नहीं, बाद में उन्होंने अस्थियों

को लेने आने में भी असमर्थता जताई और आश्रम से ही गांवा विसर्जन कराने का आग्रह किया। वृद्धाश्रम के संचालकों और स्थानीय नागरिकों ने पूरे सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया। यह दृश्य केवल एक पिता की पीड़ा नहीं, बल्कि बदलते सामाजिक मूल्यों का कठोर दस्तावेज़ बन गया। इसी समय पंजाब की एक दूसरी घटना ने डिजिटल दुनिया के भ्रम को भी उजागर किया। सोशल मीडिया इम्पल्सुएंसर कंचन कुमारी (कमल कौर) के लाखों फॉलोअर्स थे। उनकी हर पोस्ट पर हजारों ‘लाइक’ और ‘कमेंट’ आते थे।लेकिन जब उनकी दुखद मृत्यु के बाद अंतिम यात्रा निकली, तब उन लाखों डिजिटल प्रशंसकों में से कोई भी कंधा देने नहीं पहुँचा। अंतिम विदाई में केवल तीन निकट संबंधी उपस्थित थे। यह दृश्य बताता है कि सोशल मीडिया की लोकप्रियता और वास्तविक जीवन के आत्मीय संबंध दो बिल्कुल अलग संसार हैं। इन दोनों घटनाओं का संदेश एक ही है। आज हम डिजिटल रूप से पूरी दुनिया से

जुड़े हुए हैं, लेकिन भावनात्मक रूप से अपने ही परिवार से दूर होते जा रहे हैं। ‘फॉलोअर्स’ की संख्या सामाजिक प्रतिष्ठा का पैमाना बनती जा रही है, जबकि संकट की घड़ी में वही व्यक्ति साथ खड़ा होता है जिसके साथ विश्वास, अपनापन और वर्षों का संबंध हो। मोबाइल की स्क्रीन संवेदना का चित्र दिखा सकती है, पर किसी के आँसू नहीं पोंछ सकती। ऑनलाइन भुगतान जिम्मेदारी का विकल्प नहीं बन सकता और वीडियो कॉल किसी पिता के अंतिम स्पर्श को भरपाई नहीं कर सकती। ऐसे समय में भारतीय परिवार व्यवस्था की प्रासंगिकता पहले से कहीं अधिक बढ़ जाती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपने शताब्दी वर्ष में ‘पंच परिवर्तन’ के अंतर्गत ‘कुटुम्ब प्रबोधन’ को प्रमुख सामाजिक अभियान बनाया है। इसका उद्देश्य परिवारों में संवाद, संस्कार, सामूहिकता और उत्तरदायित्व की भावना को पुनर्जीवित करना है। यह अभियान किसी एक संगठन का नहीं, बल्कि भारतीय जीवन-दृष्टि का विस्तार प्रतीत होता है, जो मानती है कि परिवार केवल साथ रहने वालों का समूह नहीं, बल्कि संस्कारों की पहली पाठशाला है।

(लेखक - वरिष्ठ पत्रकार एवं समसामयिक विषयों के विश्लेषक , जनमत जागरण के संस्थापक तथा संपादक हैं.)

युवाओं को राहत लेकिन मुद्दे भी हल करें

सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले आंदोलनकारियों के खिलाफ दायर एफआईआर वापस ले ली जाएं. यह निर्देश छात्रों, पुलिस व अदालतों को राहत देने वाला है. यद्यपि कॉलेजों को राहत मिली है कि जो पूर्व अपना आंदोलन वापस ले लिया और राज्यों ने भी घोषणा कर दी कि वह मामले वापस ले लेंगे, लेकिन फिर भी भय व्याप्त था कि युवाओं पर अभियोजन कायम रह सकता है. इसकी वजह यह थी कि पहले सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को कोई दंडात्मक कार्रवाई न करते हुए जांच जारी रखने की अनुमति दी थी. अब देश की सबसे बड़ी अदालत के स्पष्टीकरण के बाद आंदोलनकारियों को राहत मिली है कि जो हो गया सो हो गया ! अब वही संदिग्ध लोग आरोप के घेरे में आएंगे, जिनका नाम दुष्कर्म और हत्या जैसे अपराधों में लिया गया है. जेन जी के इस आंदोलन में प्रदर्शन प्रायः शांतिपूर्ण रहा और सार्वजनिक संपत्ति का खास नुकसान नहीं हुआ इसलिए यह मामले पुलिस व अदालत के लिए व्यर्थ का बोझ बन जाते तथा हजारों छात्रों की पढ़ाई में बाधा आती. उनका भविष्य भी अधर में लटक जाता. अधिकांश मामले केवल असंसदीय भाषा के इस्तेमाल को

लेकर थे, जिन्हें दखिल करने की जरूरत नहीं थी. कुछ बातें आपत्तिजनक होने पर भी गैरकानूनी नहीं होतीं. युवाओं ने गुस्से और जोश में कुछ बातें कहीं क्योंकि उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा था. उम्र की नादानी व अपरिपक्वता से भी कुछ बातें हो जाती हैं. अपने आक्रोश भरे शब्दों से 15 वर्षीय लड़की चर्चा में आ गई थी. ऐसी बातों को नजरअंदाज करना ही उचित होगा. यह देखना होगा कि आंदोलन अकारण नहीं था. लगातार होने वाले पेपर लीक के मामले, बेरोजगारी ऐसे मुद्दे थे, जो युवाओं के आक्रोश व हताशा की वजह बन गए थे. भारत में विश्व की सबसे ज्यादा युवा आबादी है. इसे हमारी डेमोक्रेसी और डेमोग्राफी की उपलब्धि तो बताया गया, लेकिन इसकी ज्वलंत समस्याओं और प्रश्नों को हल करने का ठोस उपाय नहीं किया गया. अवसरों की कमी, शिक्षा प्रणाली की गिरावट और भ्रष्टाचार, बार-बार पेपर लीक से होने वाली मानसिक व्यथा, मेहनत पर पानी फिर जाना जैसी बातों से युवाओं का ठंडिन होना स्वाभाविक था. आंदोलन के लिए यह जर्जर सिस्टम जिम्मेदार था. सरकार व प्रशासन को वास्तविक मुद्दों पर ध्यान देना होगा.

संपादकीय बोर्ड

प्रबंध संपादक : सुमीत माहेश्वरी, समूह संपादक : क्रांति चतुर्वेदी

शब्द-सागर : डॉ. सागर खादीवाला

CROSS WORD12341

डॉ. सागर खादीवाला

1	2	3	4	5
6		7		
			8	9
10			11	
		12		13
15		16	17	
		18	19	20
21		22	23	

बाएं से दाएं

1. औषध, उपचार, चिकित्सा, इलाज 3. होली, मदन-महोत्सव (सं.) 6. हिंडोले पर पेंग मारना 9. खेपन, एक दैत्य का नाम 10. दुष्मन 11. महोत्सव 12. हाथ से सूत कातने का एक यंत्र 13. शायर, कविता रचने वाला 15. सार्थक ध्वनि, आवाज 16. बंदर 18. महिना, मास 19. अनेक प्रकार के 21. जल के रहित भूमि, स्थान, जगह 22. नाखून 23. वनज, बोज़

ऊपर से नीचे

1. फकीर, भिखारी (उर्दू) 2. बायां,

Solution 12340

बा	धा	गा	य	न	ख
जी	रा	फि	गी	द	ड़
ग	क	ल	प	ना	क
र	ही	म	र	छो	ना
	ब	ग	दा	द	
द	र	खा	न	ह	ला
रि	क्त	जो	शी	ला	लं
या	सं	ता	न	नं	दा

ज्योतिषाचार्य पंडित प्रियंका नारायणशंकर व्यास, कोतवाली बाजार, जबलपुर (म.प्र.)

आज जिनका जन्मदिन है

वर्ष के प्रारंभ में आर्थिक स्थिति में सुधार होगा. मन में कुछ खिन्नता रह सकती है. व्यवसायिक स्थिति में सामान्यता रहेगी. यश प्रतिष्ठा के प्रति सतर्क रहें. विलासिता की वस्तुओं का संचय होगा. वर्ष के मध्य में ध्यान देने पर स्वास्थ्य में सुधार होगा. चिकित्सक की सलाह उपयोगी रहेगी. वर्ष के मध्य में यात्रा प्रवास का योग है. कार्यक्षमता में वृद्धि होगी. वर्ष के अन्त में अधिकारियों से मेल मिलाप बढ़ेगा. मेघ और बुध्दिक राशि के व्यक्तियों को स्वास्थ्य में सुधार होगा. वृष और तुला राशि के व्यक्तियों को व्यापार में विशेष परिश्रम करना होगा. कर्क राशि के व्यक्तियों को स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है, सिंह राशि के व्यक्तियों को कार्य क्षमता में वृद्धि होगी. मिथुन और कन्या राशि के व्यक्तियों को वर्षान्त में सावधानी रखें. मकर और कुंभ राशि के व्यक्तियों को सुखद एवं धार्मिक यात्रा में वृद्धि होगी.



मेघ- धीमी गति से चल रही योजनाओं पर ध्यान दें. दौड़धूप अधिक होगी. लाभ मिलेगा.



वृषभ- पूज्य व्यक्ति की सलाह लाभदायक रहेगी. महत्वपूर्ण कार्यों की रूपरेखा बन सकती है.



मिथुन- आपके साहस एवं पराक्रम में वृद्धि होगी. कामकाज कल पर न टालें.



कर्क- प्रापर्टी के कार्योंमें सावधानी रखें. किसी अजनबी से मुलाकात लाभदायक सिद्ध होगी.



सिंह- विपरीत स्थिति को अपने लिये अनुकूल बना लेंगे. विद्या के क्षेत्र में सफलता मिलेगी.



कन्या- विरोधी वर्ग उग्र रूप धारण कर सकते हैं. लाभदायक काम बनने का योग है.



तुला- कार्य क्षेत्र में समझौता करना लाभदायक रहेगा. सुख, सम्मान, प्रतिष्ठा बढ़ेगी.



बुध्दिक- प्रतियोगी परीक्षा में सफलता के आसार हैं, सहयोगी आपकी मेहनत का लाभ उठावेंगे.



धनु- पारिवारिक मित्रों से मुलाकात सुखद रहेगी. वाहन चलाने में सावधानी रखें.



मकर- रूखे व्यवहार से मित्र वर्ग नाराज हो सकते हैं. कामकाज में व्यस्तता रहेगी.



कुम्भ- जल्दबाजी में लिया गया निर्णय नुकसानदायक हो सकता है. नए कार्य की योजना बनेगी.



मीन- कानूनी मामले में आपका पक्ष मजबूत होगा. अनुभव का लाभ मिलेगा.

मध्य क्षेत्र की डायरी

सिस्टम फेल तो सवाल उठेंगे

इन दिनों मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल सुर्खियों में है. शहर के तकरीबन 11 क्षेत्रों में 1000 दुकानों को रिहायशी इलाकों से हटाने के निर्देश के बाद हड़कंप मचा हुआ है. निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि नगर निगम इसके लिए सबसे बड़ा दोषी है.

नियम कानून को ताक पर रखकर कहीं भी कमर्शियल गतिविधियों को संचालित होते देखकर भी आंखें मूंद लेना नगर निगम की सबसे बड़ी भूल कही जा सकती है. इसकी वजह कुछ भी रही हो लेकिन नगर निगम ने सरकार को भी बड़ी मुसीबत में डाल दिया है. सबसे हैरानी की बात यह है कि पिछले दो दशकों से शहर बिना मास्टर प्लान के दौड़ रहा था, लेकिन किसी ने रिहायशी इलाकों में अवैध कमर्शियल गतिविधियों को रोकने की हिम्मत नहीं दिखाई. निस्संदेह इस मामले में मध्यप्रदेश सरकार की बहुत किरकरी हुई है. सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री स्तर पर बनाई गई 10 सदस्यीय सरकारी समिति को भंग कर दिया है और कड़ी फटकार लगाते हुए सख्त लहजे में कहा है कि जब मामले की सीधी निगरानी उच्चतम न्यायालय कर रहा है तो इसके समानांतर कोई अन्य जांच अथवा सरकारी राहत समिति बनाकर कार्रवाई को प्रभावित नहीं किया जा सकता. सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश सरकार और उसके आला अधिकारियों को भी चेतावनी दी है कि अगर किसी ने इस मामले में अनुचित हस्तक्षेप करने की कोशिश की तो उनके खिलाफ अवमानना (कंटेप्ट ऑफ कोर्ट) की कार्रवाई की जाएगी. उच्चतम न्यायालय के इस फैसले के बाद व्यापारी मायूस हैं तो रहवासियों में खुशी की लहर है. सुप्रीम कोर्ट के इस कड़े रुख के बाद अरेरा कालोनी, रोहित नगर, बावड़ियांकला, कोलार रोड, लालघाटी, चूना भट्टी, मनीपुरम, अशोक गार्डन, कोहेफजा, बैरागढ़, गिन्नौरी एवं करोड़ जैसे इलाकों के रहवासियों का कहना है कि हमें विश्वास था कि हमारी जीत होगी. वहीं, इन क्षेत्रों के व्यापारियों की शिकायत यह है कि सरकार ने इनके तर्कों को सुप्रीम कोर्ट में दमकारी से नहीं रखा. सरकार के वकील ने कोर्ट को बताया कि 101 दुकानों सील की गई है. वहीं, नगर निगम ने कोर्ट में कहा कि 1000 परिसरों को अब तक नोटिस दिए गए हैं जबकि सुनवाई में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े भोपाल के रहवासी संगठनों ने नगर निगम को कार्रवाई की पोल खोल कर रख दी. उनका आरोप था कि नगर निगम के अमले ने सिर्फ पंचनामा बनाकर ऐसे ही छोड़ दिया है. कई दुकानें फिर से खुल गई हैं तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? वहीं, सुप्रीम



कोर्ट ने नगर निगम से रिहायशी इलाकों में कमर्शियल गतिविधियां बंद कर तीन सप्ताह में रिपोर्ट मांगी है, साथ ही शीर्ष अदालत ने मध्यप्रदेश हाईकोर्ट से व्यापारिक प्रतिष्ठान चलाने वालों को दिए गए सभी स्ट्रे आर्डर को निरस्त कर दिया है. फिलहाल बताया जा रहा है कि नगर निगम ने कमर्शियल प्रतिष्ठानों पर तीन हफ्ते के लिए कार्रवाई टाल दी है. नगर निगम का तर्क है कि सुप्रीम कोर्ट में पहले पेश किए गए सर्वे को सर्वोच्च न्यायालय ने पर्याप्त नहीं माना है. इसलिए फिर से नगर निगम द्वारा पूरे शहर का व्यापक सर्वे कराया जाएगा और इस दौरान जहां भी अवैध निर्माण अथवा रहवासी इलाकों में गैर कानूनी व्यवसायिक गतिविधियां मिलेंगी, वहां कार्रवाई शुरू होगी. क्योंकि नगर निगम को कार्रवाई की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश करना होगा. हालांकि नगर निगम द्वारा पहले चरण में 429 कमर्शियल प्रांपर्टी को नोटिस जारी किए गए थे. वहीं, दूसरे चरण में नगर निगम ने 1250 से अधिक नोटिस जारी किए थे लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस संप्ल साइज को बहुत छोटा माना है. यह भी बताया जा रहा है कि अब हर विधानसभा क्षेत्र में नोडल अधिकारी नियुक्त होंगे और ये बिल्डिंग परमिशन के उद्घेधन एवं व्यावसायिक गतिविधियों का संयुक्त सर्वे कराकर सरकार को रिपोर्ट देने के लिए जिम्मेदार होंगे. यह भी कहा जा रहा है कि रिपोर्ट में गड़बड़ी करने वाले नोडल अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी. सबसे विडंबना की बात है कि मास्टर प्लान 2047 एक साल से मंजूरी का इंतजार कर रहा है. सूत्र बताते हैं कि पूरे प्रदेश में नगर निगम और नगर परिषद के कामकाज को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं. यह कहने में कोई संकोच नहीं कि पारदर्शी तरीके से लोगों का काम नहीं हो रहा है. एक छोटा से काम के लिए भी दस बार फोन करिए अथवा आला अधिकारी से निवेदन करिए तब जाकर समस्या का समाधान होता है. नगर निगम की मनमानी से लोग आजिज हैं. इसके बावजूद इसका अमला सुधरने का नाम नहीं ले रहा है. जाहिर है ऐसे में सरकार की बदनामी होती है. इससे करे कोई भरे कोई वाली कहावत चरितार्थ होती है. देखने वाली बात होगी कि सरकार कैसे इनकी खामियां दूर करती है. वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है कि सिर्फ भोपाल में ही नहीं बल्कि पूरे देश में रिहायशी इलाकों में कमर्शियल गतिविधियां चलाने वालों पर रोक लगेगी.

निशानेबाज

जांच एजेंसी सोई ओढ़कर शाल सिर्फ विपक्ष के खिलाफ इस्तेमाल



विष्णु भी 4 माह के लिए शेषशय्या पर योगनिद्रा में मग्न हैं. जांच एजेंसियों को भी सोने दो.

लिए जांच एजेंसियों की जगाकर सक्रिय कर देगी, तब एजेंसियां पूरे फॉर्म में आ जाएंगी. विपक्षी नेताओं और उनके समर्थकों के घरों, ऑफिसों व अन्य ठिकानों पर छापे मारे जाएंगे, तलाशी ली जाएगी और कई घंटों तक कड़ी पूछताछ की जाएगी. विपक्ष नेता से पूछा जाएगा बताओ, जेल जाओगे या बीजेपी की फ्रंट लोड वाली वॉशिंग मशीन में धुलकर बेदाग होना चाहोगे? सरकार के समर्थक बनकर सेफ हो जाओ और नमो-नमो जपना शुरू कर दो.' पड़ोसी ने कहा, 'निशानेबाज, सत्ता के सामने सयानापन नहीं चलता. सत्ताधीश अपने विरोधियों को सबसे पहले अंदर कर देते हैं. जांच एजेंसियां

बगैर ठोस सबूत, मनमाने आरोप लगा देती हैं. बाद में कोर्ट बेदाग बरी कर देता है. केजरीवाल, मनीष सिंसोदिया के साथ यही हुआ. सरकार के पास अलादीन का चिराग है जिसे रगड़ते ही जांच एजेंसी रूपी जिन्न प्रकट होता है. वह पूछता है- क्या हुक्म है मेरे आका, कहाँ डालना है छपा ? किसका घमंड करना है चूर, दलबदल के लिए किसे करना है मजबूर? बताइए किस पार्टी को तोड़ना है, आपको किससे नाता जोड़ना है. किस विपक्षी नेता की खत्म करनी है अकड़ और बनाए रखनी है आपकी मजबूत पकड़? सत्ताधीश कहेंगे हमें पूरी तरह तैयार, सोचकर बताएंगे कि कब किस निशाने पर करना है वार !'

SUDOKU7473

		2						4
		6						1
5		8		2				3
							6	
3					8			
1	6			3		7		
2				5				
8			4					

प्रत्येक पंक्ति में 1 से 9 तक के अंक भरे जाने आवश्यक है. इनका क्रमवार होना आवश्यक नहीं है. आड़ी और खड़ी पंक्ति में एवं 333 के वर्गों में किसी भी अंक की पुनरावृत्ति न हो इसका विशेष ध्यान रखें. ■ पहले से मौजूद अंकों को आप हटा नहीं सकते. ■ पहेली का केवल एक ही हल है.

नवभारत से-दोहू 7472

6	5	4	3	1	9	7	2	8
7	2	3	5	8	4	9	6	1
8	9	1	7	2	6	3	4	5
1	7	2	8	3	2	5	9	4
4	3	8	9	6	5	1	7	6
5	6	9	4	7	1	8	3	2
2	8	7	1	4	3	6	5	9
9	1	6	2	5	7	4	8	3
3	4	5	6	9	8	2	1	7